प्रेषक,

1707/XXXIV-3108-02(115)05.TC

हरिश्चन्द्र जोशी, सचिव,

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में.

निदेशक.

विद्यालयी शिक्षा,

उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुमाग-3

देहरादून: दिनॉक 11 फरवरी, 2008

विषयः वित्तीय व

वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वालू वृहद निर्माण कार्या

हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पन्न संख्या 581/46274/एस0सी0पी0/2007-08, दिनॉक 06 नवम्बर, 2007 एवं शासनादेश संख्या 437/XXIV-3/05, दिनॉक 27 12.2005 तथा शासनादेश संख्या 25/XXIV-3/06, दिनॉक 25.1 2006 के संदर्भ में मुझे या कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 08 (आठ) राजकीय इण्टर कालेज/राठउ०माठविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ-4 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-5 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 135.4/ लाख (रु० एक करोड, पैतीस लाख, सैवालिस हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या: 1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक 03.8 2007 द्वास आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रु० 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्य स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

क0 सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाग	आगणन की अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत घनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	रा० इ० का०, ल्वेशाल, नैनीताल	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	49.50	32 00	17.50
2	रा० उ० मा० वि०, पोखरी नैनीताल	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	51.47	, 32 00	19.47
3.	रा० ७० मा० वि०, गरजोली, नैनीताल	उत्तराखण्ड पेवजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	43,31	32 00	11/31
4.	रा० उ० मा० वि०, ऊँचाकोट नैनीताल	उत्तराखण्ड पेयजल संसन्धन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	45.64	32 00	13 64
5.	रा० छ० मा० वि०, गहना, नैनीताल	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	49 00	32.00	17.00
6	रा० उ० मा० दि०, जगलियागाद, नैनीताल	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल	51.50	12.00	19.50
7.	रा० इ० का०, रोडीपाजी, पिथीरागढ	उताराखण्ड पेक्जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रानीखेठ, अल्मोड़ा	51.80	30,00	21 80
8.	रा० इ० का०, उन्हें, पिथारागढ	चलराखण्ड पेयजल संसद्धन विकास एवं निर्माण निगम, रानीखेत, अल्मोडा	45.25	30.00	15 25
	योग-				135.47

(स्त एक करोड़, पैतीस लाख, सैतालिस हजार मात्र)





उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डी में स्थित होने पर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

आगणन में उत्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से 2-ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया 3-

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नामें है, स्वीकृत नामें से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्यों को समयबद्ध ढग से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण 4-किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार 5-

राक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त आपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

कार्यं कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण

टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा

ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानवित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी स्वीकृत घनराशि से 10-अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

जीवपीवडब्ल्यू फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल 11-

लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

किसी भी कार्यालय / संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातच्य एवं नार्मस के अनुसार गीउत किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते 13-समय कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां 14-आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर





क्राक्षाः -+3

ली जाय। स्वीकृत बनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खलकृद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-मध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत-02-अ०सू०जा० के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0201-अ०सू० जी०बाहुल्य क्षेत्रों में राठहा० / इण्टर कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—809(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—3/07 दिनोंक 31 दिसम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(हरिश्चन्द्र जोशी)

सचिव

भवदीय.

संख्या—1707(1) / XXIV-3/07/02(115)/2005 T.C., तद्दिनॉक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूबनार्च एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

- 3 निजी सचिव माठ शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

6- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल-नैनीताल।

6- अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

7— अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल—नैनीताल।

8— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सियवालय।

9- जिलाधिकारी, नैनीताल / पिथौरागढ ।

10- कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ।

11- जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल/पिथाँरागढ।

12- सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।

13- विता विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।

14- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सविवालय।

15/ एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

16- गार्ड फाइल।

आज़ा से,

(पी०एल०शाह) उप सचिव

अणि